

न्यायालय सभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या -145/2017 अपील (RCMS/2017/00078)

पंजीयन दिनांक -20.11.2017

निर्णय दिनांक -31.12.2018

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता शेरसिंह रावत, निवासी उदामान का कोट, भीम तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्त

बनाम

1. श्री पवनकुमार पिता श्री रोशनलाल गन्ना, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द।

—रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री कमलेश चौहान — वकील अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम प्रकरण संख्या 15/2013 दिनांक 01.06.2017

सत्यमेव जयते

दिनांक 31.12.2018

अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम प्रकरण संख्या 15/2013 दिनांक 01.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट श्री पवन कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम पटवार हल्का भीम जिला राजसमन्द की जमाबन्दी 2067-2070 के खाता संख्या 547 के खसरा संख्या 16554/8792 रकबा 1.03 बीघा किस्म बंजड़ उसके खरीदशुदा खातेदारी की कृषि भूमि आई है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 16554/8792 की भूमि संबंधी ही विवाद है, सही सीमा जानकारी नहीं होने

से प्रार्थी एवं अप्रार्थी में लड़ाई झगड़ा रहता है, लक्ष्मण सिंह द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए केवल मात्र आराजी नम्बर 16554/8792 की पक्की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हूँ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक जिला कलक्टर, भीम द्वारा प्रकरण दर्ज कर उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प भीम में दिनांक 01.06.2017 को रख श्री पवनकुमार के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी कर निर्णय दिनांक 01.06.2017 को पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2017 से क्षुब्ध होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्त उपस्थित। रेस्पोंडेंट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्त की एकतरफा बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने बहस में बताया कि अपीलान्त भुतपूर्व सैनिक होकर विवादित जमीन पर उसके पिता के जीवन काल से ही काबिज है। जिलाधीश, उदयपुर के आदेश राजस्व अपील संख्या 64 सम्बत् 2008 में उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्त के पिता शोरा उर्फ शेरसिंह का कब्जा प्रोटेक्ट टीनेन्ट के रूप चला आ रहा था, उसके कब्जे को विधिवत कब्जा मानकर दिनांक 14.07.1952 को शोरा के विरुद्ध गोमा पुत्र दुदा रावत निवासी भीम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं शोरा के कब्जे को वेलिड माना है। हाल सेटलमेंट में नाथू पुत्र तोलाराम महाजन केसरीमल जवाहरमल पिसरान श्री बिरदीचन्द्र के नाम गलत खोतदारी दर्ज कर दी, जबकि इन्द्राज जिलाधीश, उदयपुर के आदेशानुसार की जानी थी। साबिक खसरा नम्बर 6705 हाल खसरा नम्बर 8792 और उससे बने नये खसरा नम्बर 16554/8792 व अन्य खसरान की भूमियां शोरा व शोरा के बाद उसके पुत्रगण लक्ष्मणसिंह आदि के नाम दर्ज की जानी थी। रेस्पोंडेंट संख्या-1 का कब्जा उक्त भूमि पर कभी नहीं रहा, यह उसकी खरीदशुदा भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन की दिनांक से पूर्व पवनकुमार द्वारा वर्ष 2010 में उक्त भूमि विक्रय कर दी, जिसकी नामान्तरकरण 4071 निर्णय दिनांक 22.12.2010 से प्रमाणित होता है। शेष भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण 4291 दिनांक 20.02.2012 को स्वीकृत हुआ। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा अधिपत्य होने से तत्कालीन जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा इसी भूमि के संबंध में प्रस्तुत किये गये गोमा के दावे को निरस्त करने का आदेश दिनांक 14.07.1952 को पारित किया। पवन कुमार तो मात्र उक्त भूमि में 0.00.02 दो बिस्वार्शी भूमि अर्थात् 2/460 वे हिस्से का खातेदार रहा था जिसे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। उक्त भूमि कृषि से अकृषि रूपान्तरित

हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई का अधिकारिता नहीं है।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण राजस्व केम्प में रखा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णित कर दिया। पवन कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्य हिस्सेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया व न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया, जो उक्त प्रकरण में आवश्यक था। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पर निर्णय एकतरफा बहस सुनकर गुणावगुण एवं लोक अदालत अभियान की मूल भावना व स्कोप से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा अपील के साथ संलग्न जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश राजस्व अपील संख्या 64 सम्वत् 2008 के अनुसार उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्त के पिता शेर उर्फ शेरसिंह का कब्जा प्रोटेक्ट टीनेन्ट के रूप चला आ रहा था, उसके कब्जे को विधिवत कब्जा मानकर दिनांक 14.07.1952 को शेर के विरुद्ध गोमा पुत्र दुदा रावत निवासी भीम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं शेर के कब्जे को वेलिड माना है। विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि हाल सेटलमेंट में नाथू पुत्र तोलाराम महाजन केसरीमल जवाहरमल पिसरान श्री बिरदीचन्द्र के नाम गलत खोतदारी दर्ज कर दी, जबकि इन्द्राज जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेशानुसार की जानी थी। साबिक खसरा नम्बर 6705 हाल खसरा नम्बर 8792 और उससे बने नये खसरा नम्बर 16554/8792 व अन्य खसरान की भूमियां शेर व शेर के बाद उसके पुत्रगण लक्ष्मणसिंह आदि के नाम दर्ज की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही निर्णय पारित किये जाने दौरान अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और एकतरफा निर्णय पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.06.2017 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम का निर्णय का दिनांक 01.06.2017 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

